नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 088
दि. 30.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, जमानत पर रोक के साथ कुलदीप सेंगर को जेल में रखने का आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया कि सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। सीबीआई द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत आदेश को स्थगित किया, बल्कि सेंगर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब भी दाखिल करने को कहा है। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत गया है कि इस संवेदनशील और गंभीर अपराध के मामले में न्यायपालिका किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की गंभीरता को विस्तार से रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ हुआ अपराध न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानून और समाज दोनों के लिए बेहद गंभीर संदेश देता है। उस समय पीड़िता नाबालिग थी और उस पर अपने ही क्षेत्र के प्रभावशाली जनप्रतिनिधि द्वारा यौन शोषण का आरोप सामने आया था। मेहता ने कहा कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य ही ऐसे मामलों में कठोरता बरतना है, ताकि पद, प्रभाव और रसूख के बल पर कोई आरोपी कानून से बच न सके। उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि कोई पुलिसकर्मी, सेना का अधिकारी या किसी जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसे 'एग्रेवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट' की श्रेणी में रखा जाता है, और यही सिद्धांत ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए, जिनके पास जनता का भरोसा और सत्ता दोनों होती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला साधारण नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई आरोपी जेल से बाहर आ चुका होता तो उसकी स्वतंत्रता पर विचार किया जा सकता था, लेकिन यहां स्थिति अलग है क्योंकि कुलदीप सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में सजा काट रहा है। ऐसे में जमानत पर रोक लगाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि जब तक पूरे मामले की गहन समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली हाईकोर्ट

के आदेश को प्रभावी नहीं रहने दिया जा सकता।

पूरा मामला वर्ष 2017 से जुड़ा है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। शुरुआती दौर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता और उसका परिवार लगातार न्याय के लिए भटकता रहा। हालात इतने बिगड़े कि वर्ष 2018 में पीड़िता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद यह मामला देशभर में सुर्खियों में आया और अंततः सीबीआई को सौंपा गया। जांच के बाद सेंगर के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। साल 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज के विश्वास को तोड़ने वाला है और इसके लिए कठोर सजा जरूरी है। इसके बाद सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाल ही में हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी थी। शर्तों में यह भी शामिल था कि सेंगर पीड़िता के गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और किसी भी तरह से गवाहों या पीड़िता पर दबाव नहीं बनाएगा। हालांकि, सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है और इससे पीड़िता की सुरक्षा तथा न्याय की भावना प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और जमानत आदेश पर रोक लगा दी। यह भी उल्लेखनीय है कि कुलदीप सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इसी वजह से वह अभी भी जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि निकट भविष्य में उसकी रिहाई की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक बार फिर यह संदेश देता है कि यौन अपराधों, खासकर नाबालिगों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका किसी भी तरह की नरमी के पक्ष में नहीं है। प्रभावशाली पद और राजनीतिक रसूख कानून के आगे ढाल नहीं बन सकते। अदालत का यह कदम न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है, बल्कि समाज को यह भरोसा भी दिलाता है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त कानून का सामना करना ही पड़ेगा।

भारत की सैन्य तैयारी से बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन, 79 हजार करोड़ की हथियार खरीद को मंजूरी से चीन-पाकिस्तान पर बढ़ेगा दबाव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए तीनों सेनाओं के लिए करीब 79 हजार करोड़ रुपये के हथियार और सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 2025 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसे मौजूदा सुरक्षा हालात के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद व ड्रोन गतिविधियों के बीच भारत का यह निर्णय न केवल रणनीतिक संदेश देता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि देश अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस मंजूरी के तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एक साथ मजबूत करने पर जोर दिया गया है। थलसेना को ऐसे आधुनिक हथियार और प्रणालियां मिलेंगी, जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक साबित हो सकती हैं। लोइटर म्यूनिशन सिस्टम के जरिए सेना दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक और त्वरित हमला कर सकेगी। इसके साथ ही लो-लेवल लाइट वेट रडार की तैनाती से सीमावर्ती इलाकों में छोटे और कम ऊंचाई

पर उड़ने वाले ड्रोन और यूएवी की पहचान आसान होगी। पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की मंजूरी से इसकी मारक क्षमता और रेंज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे सेना को लंबी दूरी से प्रभावी जवाब देने की ताकत मिलेगी।

ड्रोन युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी ड्रोन रोधी सुरक्षा को भी नई मजबूती दी है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम Mk-II को मंजूरी मिलने से सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में सेना की महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा और पुख्ता होगी। हाल के वर्षों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में यह प्रणाली भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। नौसेना के लिए लिए गए फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत अपनी समुद्री ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। बोलार्ड पुल टग्स की मंजूरी से बंदरगाहों में जहाजों और पनडुब्बियों की आवाजाही और सुरक्षा बेहतर होगी। हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से नौसेना की संचार व्यवस्था अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेगी। इसके अलावा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लीज पर लेने का फैसला हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने की भारत की क्षमता को नई धार देगा।

वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी कई अहम प्रणालियों को मंजूरी दी गई है। ऑटोमैटिक टेक-ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम से उड़ानों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में सुधार होगा, खासकर खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। Astra Mk-2 मिसाइल की स्वीकृति से वायुसेना को लंबी दूरी से दुश्मन विमानों को निशाना बनाने की और अधिक ताकत मिलेगी। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर की मंजूरी से पायलटों की ट्रेनिंग और भी यथार्थपरक होगी, जबकि SPICE-1000 गाइडेंस किट से सटीक हमलों की क्षमता बढ़ेगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की समग्र रणनीतिक सोच को दर्शाता है। एक तरफ जहां इससे तीनों सेनाओं की मारक क्षमता, निगरानी और आधुनिक युद्ध क्षमताओं में बड़ा सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल मिलेगा, क्योंकि इनमें से कई प्रणालियां स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत अपनी भूमिका को एक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है।

कुल मिलाकर, 79 हजार करोड़ रुपये की यह रक्षा खरीद न केवल भारत की सैन्य तैयारियों को नई धार देगी, बल्कि यह भी साफ संकेत है कि देश अपनी सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए यह फैसला निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत अब हर मोर्चे पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सतर्क दिखाई दे रहा है।

देहरादून में नस्लीय हिंसा से एमबीए छात्र की मौत ने देश को झकझोरा हेट क्राइम के रूप में पहचान की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र अंजेल चकमा की नस्लीय हमले में हुई मौत ने एक बार फिर देश में मौजूद उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। केवल उत्तर-पूर्वी पहचान के कारण अंजेल को न सिर्फ अपमानजनक नस्लीय गालियों का सामना करना पड़ा, बल्कि चाकू से किए गए हमले ने उनकी जान ले ली। 9 दिसंबर को सेलाकुई इलाके में हुई यह घटना 14 दिनों तक आईसीयू में चले जीवन-मरण के संघर्ष के बाद 27 दिसंबर को एक त्रासदी में बदल गई। इस मौत ने न सिर्फ एक होनहार छात्र का भविष्य छीना, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। घटना के सामने आने के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसे महज आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि नस्लीय घृणा से प्रेरित हिंसा करार दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अंजेल पढ़ाई के उद्देश्य से देहरादून आए थे, लेकिन उन्हें यहां अपनी पहचान के कारण निशाना बनाया गया। परिवार और समर्थकों की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी और को अपनी नस्लीय पहचान के कारण ऐसी हिंसा का शिकार न होना पड़े।

इस मामले ने कानूनी और संवैधानिक स्तर पर भी नई बहस छेड़ दी है। अंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय अपमान और हिंसा को 'हेट क्राइम' के रूप में अलग श्रेणी देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में नस्लीय आधार पर की जाने वाली गालियां और हमले न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को तोड़ते हैं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन हैं।

याचिका में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि "चिंकी", "चीनी" जैसे शब्द सिर्फ अपमानजनक नहीं, बल्कि मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले हैं, जो कई बार जानलेवा हिंसा का कारण बन जाते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति और गरिमा के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब तक नस्लीय अपमान को गंभीर अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक संसद द्वारा हेट क्राइम से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाता, तब तक अदालत अंतरिम दिशानिर्देश जारी करे, ताकि नस्लीय हिंसा और अपमान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे विशेष पुलिस इकाइयों और स्थायी नोडल एजेंसियों का गठन करें, जहां ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज हो सके और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

इस याचिका में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों, खासकर उत्तर-पूर्व से आने वाले युवाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना सरकार और संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संवेदनशीलता विकसित हो सके।

अंजेल चकमा की मौत केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि यह उस सामाजिक मानसिकता का आईना है, जिसमें अब भी रंग, चेहरे और बोली के आधार पर भेदभाव जिंदा है। यह घटना बताती है कि कानून और सख्त संदेश के बिना नस्लीय हिंसा पर लगाम लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका अब उम्मीद की एक किरण के रूप में देखी जा रही है, जिससे न सिर्फ अंजेल को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि देश में नस्लीय घृणा के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा खड़ा होने की राह भी खुल सकती है।

आज सवाल केवल एक छात्र की मौत का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है कि क्या भारत अपनी विविधता को सच में सम्मान देने के लिए तैयार है। यदि इस घटना से सबक लेकर ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो शायद आने वाले समय में किसी और अंजेल को अपनी पहचान की कीमत जान देकर नहीं चुकानी पड़ेगी।

मुंबई नगर निगम चुनाव में अंतिम नामांकन की रातः दलों ने जारी की पहली सूची, बीजेपी, कांग्रेस-वीबीए और एनसीपी ने दिखाया अपना राजनीतिक संतुलन, शिवसेना यूबीटी और मनसे ने अपनाई अलग रणनीति

(जीएनएस)। मुंबईः 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं और मतगणना अगले दिन तय है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है और इस आखिरी समय में राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत और रणनीति का परिचय दिया है। सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की, वहीं शिवसेना यूबीटी और मनसे ने उम्मीदवारों को सीधे AB फॉर्म सौंपकर अलग रणनीति अपनाई। इस तरह राजनीतिक दलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारी और शक्ति का संकेत दे दिया है। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने कुल 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सामाजिक और भाषाई संतुलन बनाए रखने का विशेष प्रयास किया गया है। सूची में कुल 48 उम्मीदवार मराठी पृष्ठभूमि से हैं। इसके अलावा 11 उत्तर भारतीय और 6 गुजराती उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। सूची में शामिल प्रमुख नामों में तेजस्वी घोसालकर, गणेश खणकर, मनीषा यादव, मिलिंद शिंदे और आकाश पुरोहित शामिल हैं। खास बात यह है कि घोसालकर हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि आकाश पुरोहित पूर्व पार्टी मंत्री राज पुरोहित के बेटे हैं। इसके साथ ही विपक्ष के पूर्व नेता रवि राजा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और वह धारावी के वार्ड नंबर 185 से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की यह सूची राजनीतिक संदेश देने और अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने का स्पष्ट उदाहरण है।

कांग्रेस ने अपने 70 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जो वीबीए के साथ सीट समझौते के तुरंत बाद आई है। कांग्रेस-वीबीए गठबंधन 227 सदस्यों

वाले बीएमसी चुनाव में साथ लड़ रहा है। इस गठबंधन के तहत वीबीए 62 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) ने अपने छह उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आरएसपी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतर रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने मुंबई में सात सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। एनसीपी (एसपी) ने विरोधी महा विकास अघाड़ी के घटक होते हुए भी किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार गुट की एनसीपी ने गठबंधन कर चुनावी रणनीति मजबूत की है। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं और उनकी सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए यह गठबंधन किया गया है। शिवसेना यूबीटी और मनसे ने नामांकन प्रक्रिया में अलग रास्ता अपनाया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवारों को AB फॉर्म सौंपे और अनुभवी, भरोसेमंद और पुराने नेताओं पर भरोसा किया। इस बार शिवसेना ने 56 उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म सौंपे हैं। मनसे ने 15 उम्मीदवारों को तैयार किया। यह रणनीति दर्शाती है कि दोनों दल अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के साथ-साथ चुनावी जोखिमों से बचाव करना चाहते हैं।

इस अंतिम नामांकन की रात में राजनीतिक दलों ने न केवल अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर तैयारी दिखाई, बल्कि यह भी संकेत दिया कि आगामी चुनाव में सामाजिक संतुलन, स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन की रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी ने अपनी सूची में सामाजिक और भाषाई विविधता को शामिल करके यह संदेश दिया है कि स्थानीय और मराठी नेतृत्व को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं, कांग्रेस-वीबीए गठबंधन ने विपक्षी दलों के खिलाफ साझा रणनीति अपनाकर अपनी ताकत बढ़ाई है। नामांकन की अंतिम तारीख तक दलों द्वारा जारी की गई सूचियों और गठबंधनों ने चुनावी माहौल को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और जटिल बना दिया है। बीएमसी चुनाव में प्रत्याशियों का चयन, गठबंधन रणनीति और सामाजिक संतुलन की बारीकियां आगामी चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। यह अंतिम नामांकन की रात संकेत देती है कि सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और 15 जनवरी को होने वाले चुनाव तथा अगले दिन की मतगणना कई राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है।

इस चुनावी कड़ी तैयारी और अंतिम नामांकन की रात ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई के नगर निगम चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए अपनी शक्ति, रणनीति और जनता में प्रभाव दिखाने का अहम मंच है। आगामी सप्ताह में परिणामों के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा दल और गठबंधन किस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर पाया है और शहर के राजनीतिक समीकरण किस दिशा में बदलेंगे।

संपादकीय

छात्रों में एकाग्रता-रचनाशीलता को मिलेगा बढ़ावा

ऐसे समय में जब तकनीक ने जीवन को अभूतपूर्व गति दे दी है और मोबाइल, टैबलेट व लैपटॉप बच्चों की दुनिया का केंद्र बनते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय निस्संदेह एक सुखद और आशावादी संकेत है। आज का बच्चा जिस दुनिया में आंखें खोल रहा है, वहां सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन विश्वसनीय जानकारी का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल मीडिया पर जो दिख रहा है, वही अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति बच्चों में तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे माहौल में यदि स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान दस मिनट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें तथा संपादकीय पढ़ने के लिए तय कर दिए जाएं, तो यह केवल एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं रह जाती, बल्कि सोचने और समझने की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत बन जाती है। रोज पांच कठिन शब्द उनके अर्थ के साथ ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाने की व्यवस्था बच्चों की भाषा और शब्द संपदा को समृद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

यह निर्विवाद तथ्य है कि पढ़ने की आदत किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जब बच्चे नियमित रूप से अखबार पढ़ेंगे, तो उनके भीतर स्वतः ही जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और विषयों को गहराई से समझने की इच्छा विकसित होगी। अखबार केवल खबरों का संकलन नहीं होते, बल्कि समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का दर्पण होते हैं। बच्चे जब इन पन्नों से गुजरेंगे, तो वे अपने आसपास की दुनिया को केवल देखने नहीं, बल्कि समझने लगेंगे। इससे उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, सोच व्यापक होगी और धीरे-धीरे पढ़ने की संस्कृति उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह भी स्पष्ट है कि यदि पढ़ने की आदत विकसित होती है, तो स्क्रीन टाइम अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि मन को संतोष और आनंद पढ़ने से मिलने लगता है।

आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बच्चों की उंगलियां पुस्तकों के पन्ने पलटने के बजाय मोबाइल के की-बोर्ड और स्क्रीन पर थिरकती रहती हैं। किताबें और अखबार अब उनके लिए आकर्षण का विषय नहीं रह गए हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत में पांच साल तक के बच्चे भी रोजाना दो घंटे से अधिक समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। यह केवल आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का सवाल नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ने वाले असर का भी गंभीर विषय है। एक सर्वे में यह सामने आना कि दो साल जैसी कम उम्र के बच्चे भी रोज औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, समाज के लिए चेतावनी है। इससे भी अधिक गंभीर स्थिति यह है कि लगभग एक चौथाई बच्चों की इंटरनेट तक सीधी पहुंच है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी फिल्टर या समझ के बच्चे ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सच और झूठ, सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है।

दुनिया के कई देश इस खतरे को समझने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने जैसे सख्त कदम इसी चिंता का परिणाम हैं। इसके विपरीत भारत में दस साल से कम उम्र के बच्चों तक के सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं, जहां वे ऐसे कंटेंट के संपर्क में आते हैं, जो उनकी उम्र और मानसिक परिपक्वता के अनुरूप नहीं होता। ऐसे में अखबार पढ़ने जैसी पहल बच्चों को एक संतुलित, विश्वसनीय और जिम्मेदार सूचना माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। अखबारों में प्रस्तुत सामग्री न केवल तथ्यों पर आधारित होती है, बल्कि उसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी निहित होती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय कि मॉर्निंग असेंबली के दौरान बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे, दूरदर्शिता का परिचायक है। यह पहल सभी सरकारी बेसिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए है, लेकिन निजी स्कूल भी यदि चाहें तो इसे अपना सकते हैं। वास्तव में, यदि निजी शिक्षण संस्थान भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गहरा हो सकता है। बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्हें पाठ्यपुस्तकों से बाहर की दुनिया से भी परिचित कराना उतना ही जरूरी है। अखबार इस काम को बेहद सहज और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। आज भी तमाम सर्वे यह बताते हैं कि अखबार सबसे भरोसेमंद सूचना माध्यमों में से एक हैं। खबरें कई स्तरों पर जांची जाती हैं, तथ्यों की पुष्टि की जाती है और संपादकीय मंडल की जिम्मेदारी के साथ उन्हें प्रकाशित किया जाता है। संपादक नामक संस्था अखबार की आत्मा होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पाठक तक पहुंचने वाली जानकारी भ्रामक या अप्रमाणिक न हो।

युद्ध, संघर्ष, सत्ता परिवर्तन, तख्तापलट और अस्थिरता से साल भर जूझती रही दुनिया

"साल 2025 की शुरुआत ही एक बड़े झटके के साथ हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा कार्यभार संभाला। उनकी वापसी केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा।

साल 2025 वैश्विक राजनीति के इतिहास में एक ऐसे वर्ष के रूप में दर्ज हुआ, जिसने यह साफ कर दिया कि दुनिया अब स्थिरता की ओर नहीं, बल्कि अस्थिरता, टकराव और सत्ता संघर्ष की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। यह साल लोकतंत्र और तानाशाही, शांति और युद्ध, संवाद और टकराव के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर गया। कहीं चुनावों के जरिए सरकारें बदलीं, कहीं बंदूकों की नली से सत्ता हथियाई गई, तो कहीं युद्ध और सीमित संघर्षों ने मानवता को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया। 2025 की शुरुआत ही एक बड़े झटके के साथ हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा कार्यभार संभाला। उनकी वापसी केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले से कहीं अधिक आक्रामक, राष्ट्रवादी और टकरावपूर्ण नजर आया। उनकी नीतियों ने वैश्विक व्यापार, सुरक्षा गठबंधनों और कूटनीतिक संतुलन को झकझोर दिया। अमेरिका की विदेश नीति फिर से "अमेरिका फर्स्ट" की राह पर लौटती दिखी, जिससे यूरोप से लेकर एशिया तक सहयोगी देशों में असहजता बढ़ी। ट्रंप की शैली ने मित्र देशों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका अब भरोसेमंद साझेदार रह गया है।

इसके अलावा, 2025 में कई देशों में नई सरकारों का गठन हुआ। कुछ देशों में यह सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम था, तो कुछ जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता की देन। अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के कई छोटे-बड़े देशों में चुनावों के बाद नए नेतृत्व सामने आए। इन सत्ता परिवर्तनों ने यह दिखाया कि लोकतंत्र अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट

हुआ कि लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं। कई देशों में कमजोर जनादेश, बिखरी संसद और अस्थिर गठबंधन सरकारों ने शासन को चुनौतीपूर्ण बना दिया।

हम आपको बता दें कि जहाँ कुछ देशों ने चुनावों का रास्ता चुना, वहीं 2025 तख्तापलटों का भी गवाह बना। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेना ने लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता परिवर्तन की यह प्रवृत्ति खासतौर पर उन क्षेत्रों में दिखी, जहाँ पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और आतंकवाद मौजूद था। सेना द्वारा कई देशों में सत्ता पर कब्जा यह संकेत देता है कि कई देशों में लोकतंत्र अभी भी जड़ें नहीं जमा पाया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चेतावनियों और प्रतिबंधों के बावजूद तख्तापलटों का सिलसिला यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वैश्विक व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम है?

इसके अलावा, साल 2025 में दक्षिण एशिया की उथल-पुथल की कहानी में नेपाल एक अहम उदाहरण बनकर सामने आया, जहाँ सत्ता परिवर्तन की पटकथा किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि जेन-जी आंदोलन ने लिखी। बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अवसरों की कमी से त्रस्त युवा पीढ़ी ने सड़कों पर उतरकर पारंपरिक राजनीति को सीधी चुनौती दी। सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते-ही-देखते जनआक्रोश में बदल गया, जिसने सरकार की नींव हिला दी। प्रदर्शन इतने व्यापक और उग्र हुए कि सत्ता प्रतिष्ठान को झुकना पड़ा और अंततः सरकार गिर गई। नेपाल का यह घटनाक्रम इस बात का संकेत बना कि अब सत्ता परिवर्तन केवल संसद या बंदूक से नहीं, बल्कि डिजिटल पीढ़ी की संगठित आवाज़ से भी संभव है। यह आंदोलन केवल सरकार विरोधी नहीं था, बल्कि दशकों से जमी हुई राजनीतिक जड़ता और वंशवादी राजनीति के खिलाफ खुला विद्रोह था, जिसने पूरे क्षेत्र को यह चेतावनी दी कि युवा पीढ़ी को नजरअंदाज करना अब सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।

इसके अलावा, साल 2025 को यदि किसी एक शब्द में समेटा जाए तो वह शब्द है संघर्ष। यह वर्ष दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सुलगती सीमाओं, टूटते समझौतों और बढ़ते सैन्य टकरावों का गवाह बना। दक्षिण एशिया से लेकर मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया तक, शांति केवल काग़ज़ों में सिमट कर रह गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव और तनाव पूरे साल बना रहा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच कितनी नाजुक स्थिति है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा संघर्ष ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा किया, जहाँ आतंकवाद, शरणार्थी संकट और सैन्य झड़पें एक-दूसरे में घुलती रहीं।

साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया में दुनिया ने एक अप्रत्याशित मोर्चा खुलते देखा, जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमित युद्ध छिड़ गया। यह संघर्ष इस बात का संकेत था कि क्षेत्रीय विवाद, जो वर्षों से दबे हुए थे, अब खुलकर हिंसक रूप लेने लगे हैं। वहीं मध्य-पूर्व में इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष ने भयावह मानवीय संकट को जन्म दिया। गाज़ा पट्टी युद्धभूमि में तब्दील होती रही, जहाँ हवाई हमले, रॉकेट फायरिंग और ज़मीनी कार्रवाई ने हज़ारों निर्दोष लोगों की जान ली। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करता रहा।

इसके अलावा, मध्य-पूर्व में तनाव और गहरा हुआ। ईरान और इज़राइल के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। मिसाइल हमले, हवाई हमले और सैन्य चेतावनियों ने यह साफ कर दिया कि एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। इसके अलावा, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध 2025 में भी थमता नजर नहीं आया। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। साथ ही अफ्रीका के सैहेल क्षेत्र में चरमपंथी हिंसा और गृहयुद्ध जैसी स्थितियां बनी रहीं, जहाँ आम नागरिक सबसे बड़े शिकार बने।

इसी तरह बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक संघर्ष और हिंसा ने यह दिखा दिया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर पनपने वाले टकराव भी किस तरह देश को अस्थिर कर सकते हैं। विरोध-प्रदर्शन, राजनीतिक टकराव और अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता ने सामाजिक ताने-बाने को कमजोर किया।

देखा जाये तो इन सभी संघर्षों ने 2025 में यह साफ कर दिया कि दुनिया किसी एक महायुद्ध की ओर नहीं, बल्कि एक साथ कई छोटे-छोटे युद्धों और स्थायी अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। यह वह दौर है जहाँ सीमाएं बारूद बन चुकी हैं और शांति सिर्फ भाषणों तक सिमट गई है।

इसके अलावा, जहाँ दुनिया संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रही थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2025 के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बने रहे। हालांकि उनकी लोकप्रियता सर्वसम्मत नहीं थी। एक ओर उनके समर्थक उन्हें मजबूत, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेता मानते रहे, वहीं दूसरी ओर आलोचक उन्हें विभाजनकारी और संस्थाओं को कमजोर करने वाला नेता बताते रहे। ट्रंप की लोकप्रियता दरअसल इस बात का प्रतीक बनी कि दुनिया भर में राजनीति अब सहमति नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण से चल रही है।

बहरहाल, 2025 ने यह साफ कर दिया कि दुनिया अब पुराने संतुलन की ओर नहीं लौटने वाली। सत्ता परिवर्तन, तख्तापलट, युद्ध और वैचारिक टकराव आने वाले वर्षों की भूमिका लिख चुके हैं। यह साल इस सच्चाई का आईना बन गया कि शांति अब अपवाद बनती जा रही है और संघर्ष नई सामान्य स्थिति। यदि वैश्विक नेतृत्व ने समय रहते संवाद, कूटनीति और सहयोग का रास्ता नहीं चुना, तो 2025 आने वाले बड़े संकटों की शुरुआत साबित होगा।

प्रेरणा

मर्यादा में रची हँसी और प्रेम की छाया

भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक संस्कार नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और संबंधों की कोमल अभिव्यक्ति होता है। विवाह के बाद के क्षणों में जो दृश्य रचते हैं, वे जीवन भर स्मृति में बसे रहते हैं। मिथिला की परंपरा में तो इन पलों को और भी अधिक स्नेह, हास्य और मर्यादा के रंगों से सजाया जाता है। राम और सीता के विवाह के बाद का कोहबर प्रसंग ऐसा ही एक दृश्य है, जिसमें हँसी है, पर शालीनता के साथ; तर्क है, पर कटुता के बिना; और प्रेम है, पर अहंकार से परे।

विवाह संपन्न होने के बाद चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएँ अलग-अलग कक्षों में ले जाती हैं। यह क्षण नवदांपत्य जीवन की पहली सीढ़ी जैसा होता है, जहाँ संकोच, उत्सुकता और आनंद एक साथ उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण के कक्ष में सखियाँ स्वभावतः हँसी-मजाक करने लगती हैं। वे उन्हें छेड़ती हैं, पर यह छेड़छाड़ उपहास नहीं, बल्कि आत्मीयता से भरी होती है। लक्ष्मण स्वभाव से तेज हैं, पर हृदय से अत्यंत सरल और भावुक। वे सखियों की बातों को सुनते हैं, मुस्कराते हैं, पर उनके मन में अचानक एक विचार उठता है।

लक्ष्मण को अपने बड़े भाई राम का स्मरण आता है। राम अत्यंत सरल, गंभीर और मर्यादित हैं। वे किसी भी प्रकार के हास्य का उत्तर तीखे शब्दों में नहीं देते। लक्ष्मण को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं सीता की सखियाँ राम को भी इसी प्रकार छेड़ रही हों और राम अपने स्वभाव के कारण कुछ कह न पा रहे हों। यह चिंता केवल भाईचारे की नहीं, बल्कि राम की मर्यादा और सम्मान की रक्षा का भाव है। इसी भावना से प्रेरित होकर लक्ष्मण अपने कक्ष से उठकर उस कोहबर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ राम और सीता विराजमान हैं।

जैसे ही लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं, सखियाँ उन्हें देखकर खिलखिलाकर हँस पड़ती हैं। वातावरण और अधिक जीवंत हो जाता है। सखियाँ चुटकी लेते हुए कहती हैं कि अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। यह वाक्य सुनने में हल्का-फुल्का है, पर इसके पीछे मिथिला की सहजता और अपनापन छिपा है। यहाँ कोई अपमान नहीं, बल्कि नवविवाहित जीवन की मधुर शुरुआत को और भी रंगीन बनाने की कोशिश है।

सखियाँ फिर सौंदर्य की चर्चा छेड़ देती हैं। वे कहती हैं कि उनकी सखी सीता राम से अधिक सुंदर हैं और राम तो उनकी मात्र छाया हैं। यह कथन सुनते ही लक्ष्मण का स्वाभाविक भाईभाव जाग उठता है। वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि उनके आराध्य और आदर्श भैया को किसी की छाया कहा जाए। वे तुरंत प्रतिवाद करते हैं और कहते हैं कि राम अधिक सुंदर हैं और सीता उनकी छाया हैं। यह संवाद किसी कठोर बहस का रूप नहीं लेता, बल्कि सौंदर्य और प्रेम से भरी एक विनोदी तकरार बन जाता है।

तर्क-वितर्क का यह क्रम आगे बढ़ता है। सखियाँ मुस्कराते हुए कहती हैं कि निर्णय करना बहुत सरल है। वे प्रश्न पूछती हैं कि छाया का रंग कैसा होता है। लक्ष्मण बिना अधिक सोचे उत्तर देते हैं कि छाया काली होती है। उनका उत्तर सामान्य अनुभव पर आधारित है। पर यही उत्तर सखियों के लिए विजय का आधार बन जाता है। वे हँसते हुए कहती हैं कि सीता तो गोरी हैं और राम श्याम वर्ण के हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि राम, सीता की छाया हैं।

यह सुनकर लक्ष्मण निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास इस तर्क का तत्काल कोई उत्तर नहीं होता। वे चुप हो जाते हैं और सखियों की मुस्कान वातावरण में फैल जाती है। यह मौन हार नहीं, बल्कि विनम्र स्वीकार है। लक्ष्मण जैसे तेजस्वी और बुद्धिमान व्यक्तित्व का इस प्रकार चुप हो जाना यह दर्शाता है कि वे हास्य और मर्यादा दोनों का सम्मान करते हैं।

इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ हास्य कहीं भी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघता। सखियाँ छेड़ती हैं, पर उनके शब्दों में आदर है। लक्ष्मण प्रतिवाद करते हैं, पर उनमें क्रोध नहीं है। राम और सीता पूरे संवाद में मौन रहकर उसकी गरिमा को और बढ़ा देते हैं। राम का श्याम वर्ण और सीता का गौर वर्ण यहाँ किसी भेद या तुलना का कारण नहीं, बल्कि सौंदर्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है।

यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि सच्चा हास्य वही है, जो रिश्तों को मधुर बनाए, अहंकार को पिघलाए और वातावरण को हल्का कर दे। आज के समय में जहाँ हास्य अक्सर कटाक्ष, व्यंग्य और अपमान का रूप ले लेता है, वहाँ यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि विनोद भी संस्कारों से सजा होना चाहिए। मिथिला की सखियों का चपल विनोद और लक्ष्मण की सहज हार यह दर्शाती है कि प्रेम और सम्मान के बीच किया गया हास्य कभी भी कड़वा नहीं होता।

अंततः यह कोहबर प्रसंग केवल एक रोचक कथा नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। इसमें भाई का स्नेह है, सखियों की चंचलता है, नवविवाहित जीवन की मधुरता है और हास्य की गरिमा है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हँसी अनिवार्य है, पर वह हँसी यदि मर्यादा के साथ हो, तो वह रिश्तों को और गहरा करती है। राम-सीता के जीवन से जुड़ा यह छोटा सा प्रसंग हमें आज भी यह संदेश देता है कि प्रेम, सम्मान और विनोद जब एक साथ चलते हैं, तभी जीवन वास्तव में सुंदर और संतुलित बनता है।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में कौन मारेगा

साल 2025 भारतीय राजनीति में सत्ताधारी एनडीए के लिये विजय का वर्ष रहा। दिल्ली और बिहार में मिली निर्णायक जीत ने भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर विपक्ष के लिये यह साल निराशा, विघटन और हताशा का प्रतीक बन गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पराजित हुई और बिहार में कांग्रेस, राजद और वाम दलों का महागठबंधन लगभग साफ हो गया। लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। 2026 एक नये युद्ध का वर्ष है जहां सत्ता की जड़ें हिलाने के लिए विपक्ष फिर से प्रयास करेगा। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मार्च से मई 2026 के बीच होने वाले इन चुनावों के लिये सभी दल अभी से तलवारें निकाल चुके हैं। अभी से नेताओं के भाषणों में आग है, रणनीतियों में धार है और हर कदम सत्ता की लालसा से भरा हुआ है।

सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत किले की तरह खड़ी है, लेकिन इस किले की दीवारों पर अब लगातार भगवा हमले हो रहे हैं। 2016 में मात्र तीन सीटों पर सिमटी भाजपा 2021 में 77 सीटों तक पहुंच गयी। यह उछाल संयोग था या स्थायी चुनौती, इसका फैसला 2026 करेगा। ममता बनर्जी 213 सीटों और लगभग आधे वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता का बोझ भारी होता है। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय असंतोष अब उनके सामने खड़े बड़े सवाल हैं। भाजपा पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और बिहार की जीत के बाद उसका हौसला दोगुना है। वहीं कांग्रेस और वाम दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन उनका संकट यह है कि जनता अब उन्हें गंभीर विकल्प मानने को तैयार नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों में हो रहे बदलाव ने बंगाल की राजनीति में आग और घी का काम किया है। अल्पसंख्यक और शहरी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन चुनावी गणित को पूरी तरह पलट सकते हैं।

वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राज्य हमेशा से द्रविड राजनीति का गढ़ रहा है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता की रस्साकशी अब एक बार फिर चरम पर है। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक मजबूत स्थिति में है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की आहट साफ सुनाई दे रही है। रोजगार, नीट, बिजली दरें और प्रशासनिक अपेक्षाएं सरकार के लिये अग्निपरीक्षा हैं। अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन इस बार ज्यादा संगठित दिख रहा है। अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीसामी का दावा है कि यह मोर्चा 200 से अधिक सीटें जीत सकता है। लेकिन इस गणित को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला नाम है विजय। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम पहली बार मैदान में है और युवा वर्ग में उसका असर नकारा नहीं जा सकता। हालांकि करूर की भगदड़ की घटना ने विजय की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है।

वहीं असम को देखें तो राज्य में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते हैं। 2021 में 75 सीटें जीतने के बावजूद सत्ता विरोधी भावना अब उभर रही है। सरमा का दावा है कि एनडीए 100 से अधिक सीटें जीतेगा, लेकिन राजनीति में दावे अक्सर जमीनी सच्चाई से टकराते हैं। कांग्रेस के लिये यह करो या मरो की लड़ाई है। नये प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने चुनौती है कि वह लोकसभा चुनावों की सफलता को विधानसभा में बदल सकें। हालांकि दस साल की सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना आसान नहीं, खासकर तब जब विपक्षी वोट विभाजित हों। एआईयूडीएफ का रुख यहां निर्णायक साबित हो सकता है।

उधर, केरल की राजनीति हमेशा सत्ता परिवर्तन के लिये जानी जाती रही है, लेकिन वाम मोर्चा इस परंपरा को तोड़ चुका है। अब तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन विकास और निरंतरता के नाम पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस नीत मोर्चे के लिये यह अस्तित्व की लड़ाई है। यदि इस बार भी नाकामी हाथ लगी तो केरल में कांग्रेस और कमजोर हो जायेगी। भाजपा के लिये भी यह चुनाव अहम है। यदि एक भी सीट वह जीतती है तो केरल की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा।

इस बीच, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही है। मंत्री का इस्तीफा, दलित असंतोष और गठबंधन की कमजोरी सत्ता को अस्थिर बना रही है। द्रमुक यहां अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश में है और कांग्रेस केवल इतना चाहती है कि उसका नाम प्रदेश की राजनीति से न मिटे।

बहरहाल, 2026 के चुनाव सत्ता और विपक्ष, दोनों का इम्तिहान है। यह चुनाव केवल सरकारें नहीं बदलेंगे, यह तय करेंगे कि लोकतंत्र में विकल्प जिंदा हैं या नहीं। देखा जाये तो 2026 का रण सिर्फ सत्ता का नहीं, भविष्य का है।

अभियान

अनमोल वर्तमान और मूल्यवान इच्छाओं के बीच जीवन की सच्ची पहचान

वो सब कुछ कीमती है जो तुम पाना चाहते हो, मगर वो सब अनमोल है जो तुम्हारे पास है—यह पंक्ति सुनने में जितनी सरल लगती है, जीवन की उतनी ही गहरी सच्चाई को अपने भीतर समेटे हुए है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा आगे देखता है, उस लक्ष्य की ओर भागता है जो अभी उसकी पकड़ से बाहर है। बेहतर जीवन, अधिक धन, बड़ा पद, अधिक सम्मान, अधिक सुविधाएं—इच्छाओं की यह सूची कभी समाप्त नहीं होती। पर इसी दौड़ में वह अक्सर उस खजाने को भूल जाता है जो पहले से उसके पास है और जिसकी वास्तविक कीमत का एहसास उसे तब होता है, जब वह उससे छिन जाता है।

आज का मनुष्य भविष्य की योजनाओं में इतना उलझ गया है कि वर्तमान उसके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। हम सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा, तब खुश होंगे; जब वह हासिल हो जाएगा, तब सुकून मिलेगा। पर जीवन की विडंबना यही है कि "तब" कभी आता ही नहीं। एक इच्छा पूरी होती है और उसके साथ ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस निरंतर चाह की श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है, वह है हमारा आज—वह समय, वे रिश्ते, वह स्वास्थ्य और वह शांति, जो इस क्षण हमारे पास है। जो कुछ हम पाना चाहते हैं, वह निस्संदेह कीमती होता है। मेहनत, संघर्ष और त्याग से प्राप्त की गई उपलब्धियों का अपना महत्व है। सपने देखना, लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने के लिए प्रयास करना जीवन को गति देता है। पर समस्या तब पैदा होती है, जब ये सपने हमारी आँखों पर इस तरह छा जाते हैं कि हम अपने पास मौजूद सुखों को देखने की क्षमता खो बैठते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार के साथ हँसते-बोलते हैं, जिस शरीर से सांस लेते हैं, जिस मित्रता और प्रेम से घिरे होते हैं—ये सब हमें साधारण लगने लगते हैं, जबकि वास्तव में यही जीवन की सबसे बड़ी पूँजी हैं।

अक्सर हम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करके खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। किसी के पास हमसे बेहतर गाड़ी है, किसी का करियर हमसे ऊँचाई पर है, किसी का जीवन सोशल मीडिया पर अधिक चमकदार दिखाई देता है। यह तुलना हमारे मन में एक खालीपन भर देती है। हम भूल जाते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं, वह भी अपने जीवन में किसी और से तुलना कर रहा होगा। इस अंतहीन तुलना में न तो संतोष मिलता है और न ही शांति। उल्टा, जो हमारे पास है, उसकी कद्र धीरे-धीरे कम होती चली जाती है।

जीवन में सबसे अनमोल वे चीजें होती हैं, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। माता-पिता का स्नेह, जीवनसाथी का साथ, बच्चों की मुस्कान, मित्रों की निस्वार्थता, स्वास्थ्य की सहजता और मन की शांति—इन सबका कोई बाजार मूल्य नहीं है, फिर भी इनके बिना जीवन अधूरा है। जब ये हमारे पास होते हैं, तब हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं। पर जब बीमारी दस्तक देती है, तब समझ आता है कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान था। जब कोई अपना दूर हो जाता है, तब एहसास होता है कि उसका साथ कितना कीमती था।

मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अधिक पाने से जीवन बेहतर हो जाएगा। पर इतिहास और अनुभव दोनों बताते हैं कि अधिक होने से नहीं, बल्कि संतुलन से जीवन सुंदर बनता है। जिनके पास सीमित साधन होते हैं, पर संतोष होता है, वे कई बार उन लोगों से अधिक सुखी होते हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाएँ, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयास करते हुए भी अपने वर्तमान के प्रति कृतज्ञ रहना।

आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में हम समय की कमी का रोना रोते हैं, पर सच यह है कि हमारे पास समय है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। हम अपनों के साथ बैठकर बात करने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। हम बच्चों के बचपन को "बाद में" देखने की सोचते हैं, पर बचपन तो बाद में होता ही नहीं। हम माता-पिता के साथ समय बिताने को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि अभी तो वे साथ हैं, पर यह भूल जाते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता।

जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो हमारे पास है, वह हमेशा रहेगा। इसी भ्रम में हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर जब जीवन अचानक कोई मोड़ लेता है, तब हमें अहसास होता है कि जिन चीजों को हम मामूली समझ रहे थे, वे ही सबसे अनमोल थीं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने वर्तमान को पूरे मन से जिएँ, अपनों को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना सीखें।

खुशी किसी मंज़िल पर पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि यह यात्रा के हर पड़ाव को महसूस करने की कला है। जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह वर्तमान की खुशी से वंचित रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है, उसके लिए भविष्य अपने आप बेहतर होता चला जाता है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो मन में सकारात्मकता जन्म लेती है और वही सकारात्मकता हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है।

यह भी सच है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, अभाव भी होते हैं और संघर्ष भी। पर हर परिस्थिति में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है, जो हमें संभालता है। कभी किसी अपने की एक मुस्कान, कभी किसी मित्र का एक वाक्य, तो कभी भीतर से आती एक आशा की किरण। ये छोटे-छोटे सहारे ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इन्हें पहचानना और इनकी कद्र करना ही जीवन की सच्ची समझ है।

अंततः जीवन हमें यही सिखाता है कि पाने की चाह और पास होने की कद्र—दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। जो तुम पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो, सपने देखो और आगे बढ़ो। पर साथ ही जो तुम्हारे पास है, उसे हल्का मत समझो। क्योंकि कई बार वही साधारण लगने वाली चीजें, जीवन की सबसे अनमोल धरोहर साबित होती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं, तब जीवन की दौड़ एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाती है, जिसमें संतोष भी होता है, शांति भी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

गुजरात भिंडी उत्पादन में देशभर में अग्रसर

वर्ष 2024-25 में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर में लगभग 1.5 लाख टन भिंडी का उत्पादन हुआ

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र 2026 से पूर्व बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

(जीएनएस)। गांधीनगर, 29 दिसंबर : प्रगतिशील नीतियों, आधुनिक कृषि पद्धतियों तथा किसानों की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप गुजरात का बागवानी क्षेत्र राज्य के कृषि विकास का शक्तिशाली इंजन बना है। यह सकारात्मक प्रगति राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र 2026 से पूर्व राज्य के लिए उत्साहजनक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, जहाँ कच्छ एवं सौराष्ट्र की कृषि एवं बागवानी उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मजबूत आधार

गुजरात का बागवानी विभाग एमआईडीएच/एनएचएम (एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन/राष्ट्रीय बागवानी मिशन) जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अनेक राज्य स्तरीय प्रोत्साहक योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इन योजनाओं के तहत क्षेत्र आधारित क्लस्टर विकास, संरक्षित खेती, कटाई के बाद की ढाँचागत सुविधाएँ, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ प्लांट सामग्री पहल तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। एमआईडीएच अंतर्गत किसानों तथा एफपीओ को हाईटेक बागवानी, पॉलीहाउस, पैकहाउस, ग्रैडिंग-पैकिंग लाइन, प्रशिक्षण, बाजार कनेक्टिविटी तथा प्रदर्शनियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

भिंडी बुवाई तथा उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर

गुजरात सरकार के बागवानी निदेशक के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भिंडी के बुवाई क्षेत्रफल तथा कुल उत्पादन में गुजरात ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में लगभग 93,955 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की बुवाई हुई थी, जिसके फलस्वरूप 11.68 लाख टन उत्पादन दर्ज हुआ था। इस कुल आँकड़े में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कच्छ-सौराष्ट्र का राज्य के कुल भिंडी बुवाई क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत तथा कुल उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2024-25 के दौरान कच्छ-सौराष्ट्र के 12 जिलों में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की बुवाई हुई, जिससे लगभग 1.5 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ है।

सब्जी उत्पादन में राज्य का उल्लेखनीय योगदान

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के कुल सब्जी उत्पादन में गुजरात का योगदान 7.66 प्रतिशत रहा। उसी अवधि में कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र ने 2,32,584 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती कर 47,91,504 मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन हासिल किया है। प्रति हेक्टेयर 20.60 मैट्रिक टन उत्पादकता किसानों की बढ़ती कार्यक्षमता, सुधारी गईं कृषि पद्धतियों तथा मजबूत कृषि ढाँचे की प्रतिबिंब है।

बागवानी फसलें : कृषि विकास का आधारस्तंभ

उच्च उत्पादकता तथा अधिक आय के कारण बागवानी फसलें राज्य के कृषि विकास में अभिन्न अंग बन गई हैं। राज्य सरकार के सक्रिय कदमों तथा किसान अनुकूल नीतियों के फलस्वरूप आज बागवानी फसलें गुजरात के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र में लगाई जाती हैं, जो उनके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

वीजीआरसी 2026 : कच्छ एवं सौराष्ट्र की उपलब्धियों का मंच

यह मजबूत प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब गुजरात जनवरी-2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में कच्छ एवं सौराष्ट्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ एवं सौराष्ट्र का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के साथ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (वीजीआरई) जनवरी-2026 के दौरान उसी स्थान पर आयोजित होगा। वीजीआरसी राज्य सरकार की संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करेगी, जबकि कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियाँ दर्शाने तथा निवेश के लिए नए मार्ग खोलने का एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। वीजीआरसी 2026 भारत तथा विदेश के नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों, नवीनताओं तथा हिस्सेदारों को एक साथ लाएगी। केन्द्रित क्षेत्रीय सत्रों, प्रदर्शनियों तथा सहयोगी मंचों द्वारा वीजीआरसी इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कच्छ एवं सौराष्ट्र कृषि प्रगति तथा टिकाऊ विकास के आगामी चरण का नेतृत्व करने के लिए किस प्रकार सज्ज है।

भावनगर मंडल के स्टेशन अधीक्षक श्री दीपक कुमार गुप्ता दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) एवं केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में वर्तमान में स्टेशन अधीक्षक (भावनगर टर्मिनस) के पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार गुप्ता को उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए देश के दो अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) तथा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक (जांच में उत्कृष्टता) प्रदान किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी कि ये पुरस्कार 26 एवं 27 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित गरिमामय अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए गए। पदक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, माननीय गृह राज्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के गणमान्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रदान किए गए। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने श्री गुप्ता को बधाई दी एवं उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में अपने कार्यकाल के दौरान श्री दीपक कुमार गुप्ता ने अनेक संवेदनशील एवं राष्ट्रीय महत्व के उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें पुलवामा आतंकी हमला, जम्मू-

कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले, क्रॉस-बॉर्डर एलओसी ट्रेड, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आतंकी वित्तपोषण, आईएसआईएस से जुड़े विभिन्न मॉड्यूल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) मामला, एक उच्च-प्रोफ़ाइल हत्या प्रकरण तथा मुंबई ब्लास्ट मामला शामिल हैं। इन मामलों में उनके असाधारण योगदान एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) से सम्मानित किया गया।

एनआईए के एक प्रमुख प्रकरण में देशभर के उच्च शिक्षित युवाओं द्वारा एक ही दिन में अनेक सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश रची गई थी, जिसमें आतंकी फंडिंग कई देशों से क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से की जा रही थी। इस मामले में छह आतंकवादियों की गिरफ्तारी, सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए जाने तथा पाँच आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने में श्री गुप्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। साइबर, वित्तीय एवं क्रिप्टोकरेंसी जांच में उनकी उत्कृष्ट दक्षता एवं उच्च दबाव की परिस्थितियों में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक (जांच में उत्कृष्टता) प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में अपनी सेवाओं के दौरान श्री गुप्ता को केंद्रीय गृह मंत्री स्पेशल ऑपरेशन पदक, महानिदेशक, एनआईए की प्रशस्ति सूची, तथा अनेक प्रमाण-पत्र, प्रशंसा पत्र एवं नकद पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेल में अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान भी उन्हें विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कई बार सम्मानित किया गया है, जिनमें डीआरएम स्तर पर तीन, एसडीजीएम स्तर पर एक तथा जीएम स्तर पर दो पुरस्कार शामिल हैं।

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सी. आर. गरूडा ने बताया कि श्री दीपक कुमार गुप्ता का व्यावसायिक आचरण ईमानदारी, साहस एवं राष्ट्र के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय रेल में सेवाएँ प्रदान करते हुए भी वे अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं जनसेवा के मूल्यों को निरंतर बनाए हुए हैं। इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनका सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की पहचान है, बल्कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ राष्ट्रसेवा करने की प्रेरणा भी है।

नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का खतरनाक खेल पुलिस की सख्ती के बाद थम आठ युवक गिरफ्तार, दो वाहन जब्त – सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम

(जीएनएस)। फिरोजाबाद। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में खतरनाक करतब करने वाले युवकों के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया और इस दौरान स्टंट में इस्तेमाल दो वाहनों को सीज कर लिया। यह कार्रवाई सड़क पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और हाईवे पर हो रहे जानलेवा हादसों को रोकने के लिए की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर जिले में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टूंडला पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी।

सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर कुछ युवक हुंडई क्रेटा और महिंद्रा एक्सयूवी-700 से स्टंट कर रहे हैं और सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरा बन रहे हैं। तुरंत गश्त पर निकली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, ये युवक तेज रफ्तार में वाहन चलाकर सड़कों पर खतरनाक करतब कर रहे थे, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। इनकी इस हरकत से न केवल हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि आम जनता की जान पर भी संकट मंडरा रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान विनायक उर्फ ईशू, मनोज उर्फ हैडन, मोहित, पंकज, अभिषेक, आशीष, निखिल और यशू के रूप में हुई है। सभी

आरोपित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों के साथ स्टंट में प्रयुक्त दो वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के जोखिम को रोका जा सके।

सौरभ दीक्षित ने इस कार्रवाई को हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि सड़क पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में खतरनाक ड्राइविंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे भी ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। पुलिस ने यह साफ किया कि हाईवे पर होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त जारी रहेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी और खतरनाक ड्राइविंग न केवल सड़क पर यात्रा करने वालों के लिए खतरा हैं, बल्कि यह सामाजिक रूप से भी चिंता का विषय है। ऐसे युवा अपनी नादानी और अहंकार के कारण खुद और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की सक्रियता, कड़ी कानूनी कार्रवाई और जन जागरूकता बेहद जरूरी है।

फिरोजाबाद में यह कार्रवाई एक मिसाल साबित हुई है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई ढील नहीं बरत रही है। जिले में हाईवे पर स्टंटबाजी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के खतरनाक वाहन चलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों और पैट्रोलिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए सक्रिय निगरानी, लोगों की जिम्मेदारी और प्रभावी कानून प्रवर्तन की आवश्यकता है। हाईवे पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में खतरनाक ड्राइविंग जैसे कृत्यों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से न केवल दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी, बल्कि आम जनता में भी यह संदेश जाएगा कि सड़कें सुरक्षित और हर किसी के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए।

सारांश यह है कि फिरोजाबाद पुलिस की यह कार्रवाई हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी को रोकने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। गिरफ्तार आरोपितों और जब्त वाहनों के मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है, और पुलिस ने साफ कर दिया है कि भविष्य में इस तरह के किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वे भी सड़क सुरक्षा में पुलिस का सहयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि हाईवे पर यात्रा सभी के लिए सुरक्षित और निर्बाध बनी रहे।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली भावनगर बान्द्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

टिकटों की बुकिंग 30 दिसंबर (मंगलवार) से शुरू होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक गुरूवार को चलने वाली भावनगर-बान्द्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर स्पेशल, जिसे पहले 26 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 09.30 बजे प्रस्थान करती है और उसी दिन रात्रि 23.45 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचती है।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, जिसे पहले 25 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 26 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस स्टेशन से प्रत्येक गुरूवार को दोपहर 14.50 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन प्रातः 06.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचती है।

ट्रेन संख्या 09208/09207 की बुकिंग 30 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, विशेष किराये पर चल रही 09 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल को 30 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल – भगत की कोठी स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल – भगत की कोठी स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09084 भगत की कोठी – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल – भिवानी स्पेशल (त्रि-साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल – भिवानी स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09002 भिवानी – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09207/09208 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को भी 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम स्पेशल (साप्ताहिक)
ट्रेन संख्या 09415 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09416 गांधीधाम – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल
ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09056 उधना – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09211/09212 गांधीग्राम – बोटाद स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम – बोटाद स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09212 बोटाद – गांधीग्राम स्पेशल को भी 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09215/09216 गांधीग्राम – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम – भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09216 भावनगर टर्मिनस – गांधीग्राम स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09529/09530 धोला – भावनगर टर्मिनस स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09529 धोला जं.– भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09530 भावनगर टर्मिनस – धोला जं. स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09085, 09083, 09001, 09086, 09207, 09208, 09415, 09416, 09055 एवं 09056 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सोना वायदा 1815 रुपये और चांदी वायदा 4587 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 64 रुपये की बढ़त

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 709906.7 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 111464.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 598426.77 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 35291 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4514.68 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 89786.39 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 139808 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140444 रुपये और नीचे में 137646 रुपये पर पहुंचकर, 139873 रुपये के पिछले बंद के सामने 1815 रुपये या 1.3 फीसदी घटकर 138058 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 214 रुपये या 0.19 फीसदी गिरकर 110891 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 134 रुपये या 0.96 फीसदी गिरकर 13841 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा 137628 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138269 रुपये और नीचे में 135777 रुपये पर पहुंचकर, 1723 रुपये या 1.25 फीसदी गिरकर 136066 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 137602 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138983 रुपये और नीचे में 135100 रुपये पर पहुंचकर, 137605 रुपये के पिछले बंद के सामने 1339 रुपये या 0.97 फीसदी गिरकर 136266 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 247194 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254174 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 232663 रुपये पर पहुंचकर, 239787 रुपये के पिछले बंद के सामने 4587 रुपये या 1.91 फीसदी घटकर 235200 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3555 रुपये या 1.48 फीसदी गिरकर 236807 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3563 रुपये या 1.48 फीसदी लुढ़ककर 236865 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 111464.58 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 598426.77 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 89786.39 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35291 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 18787.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 21.7 रुपये या 1.72 फीसदी लुढ़ककर 1237.6 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 8.55 रुपये या 2.74 फीसदी गिरकर 303.1 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 5.7 रुपये या 1.91 फीसदी लुढ़ककर 293.35 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 5 पैसे या 0.03 फीसदी टूटकर 183.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2962.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5182 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5253 रुपये और नीचे में 5170 रुपये पर पहुंचकर, 64 रुपये या 1.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5246 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 59 रुपये या 1.14 फीसदी की बढ़त के साथ 5243 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 354 रुपये के भाव पर खूलकर, 356.6 रुपये के दिन के उच्च और 342.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 352.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.1 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 348.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 3.9 रुपये या 1.11 फीसदी औंधकर 348.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 978 रुपये के भाव पर खूलकर, 80 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 973.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 29682.58 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 60103.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 16317.90 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1173.15 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 65.20 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 1230.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 519.35 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2430.99 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17347 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77127 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 23775 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 361352 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 38549 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16915 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40649 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 106696 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20308 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 34309 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 36380 पॉइंट पर खूलकर, 36815 के उच्च और 35182 के नीचले स्तर को छूकर, 453 पॉइंट घटकर 35291 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 29.8 रुपये की बढ़त के साथ 167.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.15 रुपये की गिरावट के साथ 29.15 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 844.5 रुपये की गिरावट के साथ 468 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 249000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1918 रुपये की बढ़त के साथ 11736 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 17.45 रुपये की बढ़त के साथ 59.52 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.93 रुपये की गिरावट के साथ 14 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 35.6 रुपये की गिरावट के साथ 126.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 30.05 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 577.5 रुपये की बढ़त के साथ 1192 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 801 रुपये की बढ़त के साथ 3652.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 15.76 रुपये की बढ़त के साथ 40.34 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.91 रुपये की बढ़त के साथ 12 रुपये हुआ।

अयोध्या में भव्य उत्सव: कर्नाटक से आई स्वर्ण-हीरा जड़ित श्रीराम प्रतिमा का ऐतिहासिक अनावरण, श्रद्धालुओं में उमड़ा आस्था और भक्ति का जोश

(जीएनएस)। अयोध्याः रामनगरी अयोध्या में सोमवार को भक्ति और धार्मिक श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब कर्नाटक से लाई गई स्वर्ण और हीरों से जड़ित प्रभु श्रीराम की भव्य और अलौकिक प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा न केवल भव्य है बल्कि इसे देखकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और भक्ति की चमक साफ झलक रही थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस ऐतिहासिक और अद्वितीय प्रतिमा का विधिपूर्वक अनावरण किया। प्रतिमा को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित किया गया है। प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई लोग दूर-दूर से अपनी भक्ति और श्रद्धा का अनुभव लेने अयोध्या पहुंचे। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी इस अद्भुत दृश्य को देखकर अभिभूत नजर आए। भक्तों ने बताया कि पहली बार उन्होंने इतनी भव्य और दिव्य प्रतिमा देखी, जो न केवल भौतिक रूप से आकर्षक है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मन को छू लेने वाली है।

तंजौर कला में निर्मित दुर्लभ प्रतिमा

बताया गया है कि यह प्रतिमा प्रसिद्ध तंजौर कला शैली में तैयार की गई है। तंजौर शैली में बनाए गए मंदिरों और मूर्तियों की भांति, इस प्रतिमा में भी नक्काशी और अलंकृत सजावट का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पकार द्वारा निर्मित इस स्वर्ण और रत्नजड़ित प्रतिमा की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह प्रतिमा न केवल मंदिर स्थापत्य की उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसमें आध्यात्मिक सौंदर्य और दक्षिण भारतीय शिल्पकला का

अद्वितीय मिश्रण भी देखने को मिलता है।

प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी द्वितीय पाटोत्सव का आयोजन किया। राम जन्मभूमि परिसर स्थित अंगद टीला पर यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर 108 यजमानों ने विधिपूर्वक पूजन किया और श्रीरामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया गया। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और भजन-कीर्तन में सक्रिय भागीदारी की, जिससे परिसर में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ।

श्रद्धालुओं और संतों की अपार उपस्थिति

प्रतिमा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि परिसर की गलियां श्रद्धालुओं से भर गईं। लोगों ने अपने-अपने परिवार और बच्चों के साथ प्रतिमा के दर्शन किए। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार इतनी भव्य और दिव्य मूर्ति देखी। कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों में आंसू लिए भक्ति भाव व्यक्त किया।

महासचिव चंपत राय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 31 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोनों नेता राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती के पश्चात अंगद टीला प्रांगण में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। उन्होंने संतों, महात्माओं और नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 1.30 बजे अंगद टीला पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनें। ट्रस्ट ने बताया कि श्रीराम अस्पताल के पास से गुजरने वाला नया मार्ग 'सुग्रीव पथ' सीधे अंगद टीला तक जाता है और कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा।

श्रद्धालुओं ने जताई खुशी और आस्था

प्रतिमा के दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रतिमा ने उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण और हीरों से सुसज्जित यह मूर्ति न केवल आँखों को भा रही है बल्कि मन को भी आध्यात्मिक शांति प्रदान कर रही है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन और ट्रस्ट को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण इस प्रकार किया कि सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें।

भव्यता और आध्यात्मिक महत्व

प्रतिमा के अनावरण ने अयोध्या के धार्मिक महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। यह प्रतिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। स्थानीय दुकानदारों, गाइडों और श्रद्धालुओं ने बताया कि आने वाले दिनों में देश-विदेश से भारी संख्या में भक्त और पर्यटक अयोध्या आएंगे। इससे न केवल धार्मिक महत्व बढ़ेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

अयोध्या का भविष्य: धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में

भव्य अनावरण समारोह और आगामी 31 दिसंबर के विशेष कार्यक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि अयोध्या अब धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से एक अद्वितीय केंद्र के रूप में उभर रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन में संतों, महात्माओं और आम श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इसे और भी यादगार बना दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आयोजन आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा।

इस प्रकार, अयोध्या में प्रभु श्रीराम की इस स्वर्ण-हीरा जड़ित मूर्ति के आगमन ने न केवल शहर को धार्मिक दृष्टि से गौरवशाली बनाया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की अनमोल अनुभूति भी प्रदान की है।

अहमदाबाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र को लाठी से पीटने का मामला, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

(जीएनएस)। अहमदाबादः बावला स्थित बागोदरा प्राथमिक विद्यालय में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है। बताया गया है कि विद्यालय की पांचवीं कक्षा की शिक्षिका अमीबेन रावल ने एक छात्र को कथित तौर पर लाठी से पीट दिया, जिससे छात्र के हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ी। यह घटना उस समय हुई जब छात्र ने सामान्य कक्षा गतिविधियों में भाग लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के अभिभावक ने 112 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र को तुरंत अस्पताल भेजा गया और उसकी चोट का इलाज कराया गया। अभिभावक ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल न्याय सुनिश्चित करना है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन और पुलिस से इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। बागोदरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि अमीबेन रावल के खिलाफ पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पहले के घटनाओं में शिक्षक को मौखिक चेतावनी दी गई थी और उन्हें ऐसा व्यवहार न दोहराने का आश्वासन

लिया गया था। इसके बावजूद, आज की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि मौखिक चेतावनी और हल्की कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। प्रिंसिपल ने कहा कि यदि उन्हें लिखित शिकायत मिलती है, तो वे इसे टीपीओ और उच्च अधिकारियों को सौंप देंगे और जरूरत पड़ने पर शिक्षक के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। हालांकि, प्रिंसिपल की इस प्रतिक्रिया ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसी छवि पेश की। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षित रखें। यदि पहले की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई होती, तो आज छात्र को चोट नहीं लगती। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्यार और सहानुभूति के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, न कि उन्हें डर और शारीरिक नुकसान के माध्यम से अनुशासित करें। वर्तमान समय में कई शिक्षक बार-बार बच्चों पर हाथ उठाते हैं, जो कानून के तहत अपराध है। इसलिए, अमीबेन रावल के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई होना अनिवार्य है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। प्रधानाचार्य को चाहिए कि वे शिक्षक कर्मचारियों के व्यवहार पर लगातार निगरानी रखें और किसी भी अनुचित व्यवहार को तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय समाज और अभिभावक इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का भी माध्यम है।

गुजरात की सड़कें खून से सनी: बनासकांठा और ध्रांगधरा में भीषण हादसों में 4 लोगों की मौत

(जीएनएस)। गुजरातः राज्य की सड़कें एक बार फिर हादसों और त्रासदी की वजह से सुर्खियों में हैं। सोमवार रात को दो अलग-अलग जिलों – बनासकांठा और सुरेंद्रनगर – में हुए भीषण सड़क हादसों में कुल चार लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटनाएं सड़क सुरक्षा की स्थिति और तेज रफ्तार वाहनों के कारण बढ़ रहे खतरों की गंभीर चेतावनी देती हैं।

सबसे पहले बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका के लिंबोई गांव के पास एक यात्री रिक्शा और तेज रफ्तार पिकअप ट्रक की भीषण टक्कर हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, वडगाम से लिंबोई जा रहे रिक्शा में सवार दो महिलाएं – दोनों लिंबोई गांव की निवासी – मौके पर ही मौत के मुंह में चली गईं। यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों का भी पसीना छूट गया। पिकअप ट्रक चालक के खिलाफ वडगाम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस काफिला मौके पर पहुंचा और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गया। इस दुखद घटना ने पूरे लिंबोई गांव को मातम में डुबो दिया और ग्रामीणों में गहरा शोक फैल गया।

वहीं दूसरी ओर, सुरेंद्रनगर जिले में ध्रांगधरा-मालवन राजमार्ग पर एक और भयावह दुर्घटना घटी। हरिपार गांव के पास देर रात एक कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे खाई में पलटकर गिर गई। इस हादसे में कार में सवार कृपाल सिंह ज़ाला और बोनिलभाई देसाई नामक दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य दो युवकों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि राजमार्ग पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं ने प्रशासन की अनदेखी और सड़क सुरक्षा की कमी को उजागर कर दिया है। कई यात्री और स्थानीय नागरिक यह सवाल कर रहे हैं कि क्या तेज रफ्तार वाहनों और खराब सड़क किनारों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हादसों की बड़ी वजह तेज गति और ड्राइवर की लापरवाही है। रिक्शा और कार जैसे छोटे वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण ये हादसे और अधिक घातक हो जाते हैं। बनासकांठा और सुरेंद्रनगर की घटनाएं इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में सड़क सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि सड़क पर गश्त बढ़ाई जाएगी और हादसों के तुरंत बाद पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, लोग अभी भी सड़क किनारे खतरनाक मोड़ और खाई के पास उचित चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा उपाय की कमी को लेकर चिंतित हैं। सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य सरकार और संबंधित विभाग समय पर उचित कदम उठा रहे हैं। तेज रफ्तार वाहन, खराब सड़कें और सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिलकर लोगों की जान को लगातार खतरे में डाल रही हैं। बनासकांठा और ध्रांगधरा की घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए न केवल यातायात नियमों का पालन आवश्यक है, बल्कि सड़क किनारे चेतावनी संकेतक, गति नियंत्रण, और ड्राइवरों की जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं और गुजरात की सड़कें और अधिक खतरनाक बन सकती हैं। इस भयावह सिलसिले ने राज्य में सड़क सुरक्षा सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर कर दिया है। बनासकांठा और ध्रांगधरा की घटनाओं ने यह संदेश दिया है कि सड़कें सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा और सावधानी के साथ ही सुरक्षित रह सकती हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा वर्ष 2026 के लिए पश्चिम रेलवे का वॉल कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर का विमोचन

राष्ट्रीय गौरव के 150 वर्षों और भारतीय रेल की शाश्वत विरासत का दृश्यात्मक सफ़र

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी नववर्ष के अवसर पर वर्ष 2026 के लिए अपने वॉल कैलेंडर एवं टेबल कैलेंडर का विमोचन कर संगठन की गौरवशाली विरासत, समकालीन उपलब्धियों तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा पश्चिम रेलवे मुख्यालय, चर्चगेट में प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों की उपस्थिति में इन कैलेंडरों का औपचारिक विमोचन किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वॉल कैलेंडर 2026 का विषय "वंदे मातरम् – राष्ट्रीय गौरव और गौरवगाथा के 150 वर्ष" है, जो भारत के इस प्रतिष्ठित देशभक्ति गीत के डेढ़ सौ वर्षों का स्मरण करते हुए पश्चिम रेलवे की परिवर्तनशील यात्रा को प्रतिबिंबित करता है। यह आकर्षक एवं दृश्यात्मक रूप से समृद्ध कैलेंडर पश्चिम रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों और आधारभूत संरचना विकास को दर्शाता है। इसमें वंदे भारत

एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें, आधुनिक विद्युत इंजनों, उन्नत रेलवे स्टेशनों तथा एस्केलेटर और बेहतर स्टेशन संरचना जैसी उन्नत यात्री सुविधाओं के प्रमुख दृश्य शामिल हैं। ये सभी चित्र सुरक्षित, कुशल एवं विश्वस्तरीय रेल सेवाएं प्रदान करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तिरंगे के सजीव रंगों में डिज़ाइन किया गया यह कैलेंडर राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ते हुए तकनीकी नवाचार एवं यात्री-केंद्रित विकास को भी उजागर करता है।

भारतीय रेल की स्थायी विरासत को प्रतिबिंबित करते हुए और अतीत की स्मृतियों को जीवंत करते हुए, श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि टेबल कैलेंडर 2026, जिसका विमोचन भी इसी कार्यक्रम में किया गया, "इतिहास के पन्नों से गुजरती रेलगाड़ियाँ – लोकोमोटिव्स ऑन पेडेस्टल" विषय पर आधारित है और यह भारतीय रेल की गौरवशाली विरासत को समर्पित एक भावनात्मक श्रद्धांजलि है। इस कैलेंडर में पश्चिम रेलवे द्वारा संरक्षित विंटेज भाप इंजनों के मनमोहक चित्र शामिल हैं, जो उस दूरदर्शिता, समर्पण और अथक प्रयासों को दर्शाते हैं, जिन्होंने भारतीय रेल को राष्ट्रीय प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बनाया। आज जहां यात्री वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, वहीं ये कालजयी भाप इंजन हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब रेलगाड़ियाँ खेतों, कस्बों और शहरों से गुजरते हुए अपनी विशिष्ट सीटी की गूंज के साथ आगे बढ़ती थीं, जो रेल यात्रा के रोमांच, दृढ़ता और शाश्वत भावना का प्रतीक हैं।

वर्ष 2026 के लिए वॉल और टेबल कैलेंडरों का यह विमोचन न केवल पश्चिम रेलवे के गौरवशाली अतीत और गतिशील वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि राष्ट्र और यात्रियों की सेवा में नवीन ऊर्जा, नवाचार और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के उसके संकल्प को भी पुनः सुदृढ़ करता है।

हलवड़ में 30 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन हड़पने वाले घोटाले का मास्टरमाइंड रमेश सकारिया गिरफ्तार, पुलिस ने खुलासा किया बड़ा साजिश नेटवर्क

(जीएनएस)। हलवड़ः हलवड़ पंथक में सरकारी जमीनों के फर्जी रिकॉर्ड बनाकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने वाले रमेश बाबाभाई सकारिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ा घोटाला उजागर किया है। इस सुनियोजित साजिश के तहत लगभग 30 करोड़ 80 लाख रुपये मूल्य की सरकारी जमीन, यानी करीब 138 एकड़ (लगभग 344 बीघा) हड़प ली गई थी। यह जमीन हलवड़ तालुका के कोयबा, घनश्यामपुर और सुंदरीभवानी गांवों में स्थित थी।

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रमेश सकारिया ने वर्ष 2016 में मामलतदार के सामने फर्जी हस्ताक्षरों वाले दस्तावेज पेश किए। इसके बाद, 2016 से 2020 के बीच अन्य सह-आरोपियों ने भी इस गिरोह के तहत कई फर्जी आवेदन किए और सरकारी राजस्व अभिलेखों में बदलाव करवाया। इस तरह लंबी अवधि तक चलने वाली यह योजना बड़ी सावधानी के साथ अंजाम दी गई।

हलवड़ पुलिस निरीक्षक आर.टी. व्यास और उनकी टीम ने मामले की गहन जांच की। शुरुआती चरण में चार आरोपियों—छगनभाई नागजीभाई, मावजीभाई तबा राठौड़, हमीरभाई वनानी और दिनेशभाई वनानी—को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता रमेश सकारिया लंबे समय तक फरार रहा। पुलिस ने उसे

कोयबा गांव से पकड़कर हिरासत में लिया और जेल भेज दिया।

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस घोटाले में पुख्ता सबूत जुटाए हैं। अब यह जांच जारी है कि क्या इस बड़े घोटाले में किसी राजस्व कर्मचारी या उच्च अधिकारी की संलिप्तता रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में अक्सर स्थानीय अधिकारियों या जमीन रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारियों की मदद भी ली जाती है, इसलिए इस दिशा में भी छानबीन की जा रही है।

स्थानीय लोग इस मामले को लेकर आश्चर्यचकित हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जमीन पर इतने लंबे समय तक कब्जा कैसे संभव हो पाया, यह स्पष्ट रूप से प्रशासन और रिकॉर्ड रखने वाली व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है। अधिकारियों का कहना है कि रमेश सकारिया के गिरफ्तारी से अब इस पूरे गिरोह का नेटवर्क उजागर होने की संभावना है और अन्य संभावित आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की सफलता पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में ऐसे घोटालों की रोकथाम और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद हलवड़ में सरकारी जमीनों से जुड़े अन्य मामलों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और कानून का शासन मजबूत होगा।

यह मामला न केवल हलवड़, बल्कि पूरे गुजरात में सरकारी संपत्ति और जमीन अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। रमेश सकारिया की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि समय पर और कड़े कदम उठाने से बड़े घोटालों को बेनकाब किया जा सकता है। प्रशासन और पुलिस की निगरानी से अब ऐसे मामलों पर नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई है।

अहमदाबाद में सुरक्षा पर करोड़ों खर्च के बावजूद बढ़ती शिकायतें निगम ने निजी एजेंसियों पर वसूला 43.8 करोड़ का जुर्माना

(जीएनएस)। अहमदाबादः पिछले आठ वर्षों में अहमदाबाद नगर निगम ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के नाम पर 211 करोड़ रुपये से अधिक की भारी रकम खर्च की है। हालांकि, इस विशाल बजट के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा संबंधी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। निगम के विभिन्न कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा में कमी के कारण लोगों ने प्रशासन के पास कुल 1,106 शिकायतें दर्ज कराई हैं।

नगर निगम ने लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कुल 43.8 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। यह रकम मुख्य रूप से उन एजेंसियों से वसूली गई, जिन्होंने अपने दायित्वों का ठीक से पालन नहीं किया। निगम निजी एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड तैनात करता है, लेकिन फिर भी अस्पतालों, निगम कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा में चूक और विवाद की घटनाएं आम होती रही हैं।

नागरिकों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निगम

के मुख्य कार्यालय, अस्पताल या अन्य कार्यालयों में जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण उनके लिए कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। अधिवक्ता अतीक सैयद ने कहा कि एसवीपी, एलजी अस्पताल और निगम के मुख्य दानापीठ कार्यालय में सुरक्षा गार्डों और मरीजों के परिजनों या आम जनता के बीच झड़प की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में ठेका प्रणाली को बंद करके सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

नगर निगम द्वारा वसूले गए जुर्माने की सूची भी सामने आई है, जिसमें प्रमुख एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इनमें शक्ति सिक्योरिटी पर 49.52 लाख रुपये, डॉक्सन सर्विस पर 46.92 लाख, यूनिक डेल्टा पर 23.16 लाख, शिवा सिक्योरिटी पर 44.75 लाख, एस्कॉर्ट सुरक्षा पर 11.53 लाख, राजपूत सुरक्षा पर 45.16 लाख, एमके सिक्योरिटी पर 38.74 लाख, यूनिक डेल्टाफोर्स पर 23.16 लाख, शक्ति संरक्षण पर 38.33 लाख, पैंथर सिक्योरिटी पर 36.60 लाख, बालाजी सिक्योरिटी पर 8.96 लाख, जीआईएसएफएस पर 5.29 लाख और असीमा लिमिटेड पर 3.6 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि निगम द्वारा सुरक्षा पर किए गए भारी खर्च के बावजूद ऐसी घटनाओं का होना स्पष्ट संकेत है कि मौजूदा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। निजी एजेंसियों पर आधारित ठेका प्रणाली को छोड़कर निगम को स्वयं जिम्मेदार होकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। इसके तहत सुरक्षा गार्डों का प्रशिक्षण, निगरानी और तैनाती में पारदर्शिता बढ़ाना और शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाना आवश्यक है।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि उन्होंने लगातार निगरानी और निरीक्षण बढ़ाकर सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित की है, लेकिन विशेषज्ञों और नागरिकों का मानना है कि यह कदम पर्याप्त नहीं है। आगामी वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और ठेका प्रणाली में बदलाव आवश्यक होगा, ताकि नागरिकों की सुरक्षा पर खर्च की गई भारी रकम का सही लाभ उन्हें मिल सके।

यह स्थिति अहमदाबाद जैसे महानगर में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करती है, जहां लाखों लोग प्रतिदिन सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं। अब यह नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे ठेका प्रणाली में सुधार, निगरानी बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित समाधान के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी और भरोसेमंद बनाएं।

वडोदरा मंडल के बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी "कवच 4.0" प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करते के क्रम में 29 दिसंबर,2025 को 96 किलोमीटर लंबे बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

कवच से लैस पहली ट्रेन 59549/59550 संकल्प फास्ट पैसेंजर 29 दिसंबर,2025 को वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई, जिसके लोकोमोटिव में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके एवं वरिष्ठ अधिकारिओं ने सफ़र किया और इस स्वदेशी "कवच" प्रणाली का अवलोकन किया। पहली ट्रेन शत प्रतिशत ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के साथ चली और इस प्रकार बाजवा - अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी "कवच 4.0"

प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशन हुआ।

वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में रेलवे में टेक्नोलॉजी में आत्मसात किया जा रहा है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जो सिग्नल पास एट डेंजर (SPAD) की रोकथाम के साथ - साथ ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल एवं आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा जैसी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है। यह ट्रैक पर RFID टैग और ट्रैक, सिग्नल और लोकोमोटिव के बीच कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी (UHF) का इस्तेमाल करता है, जिससे केबिन में लोको पायलटों को रियल-टाइम जानकारी मिलती है, और यह सुरक्षित और ज़्यादा कुशल यात्राओं के लिए एक सतर्क रक्षक की तरह काम करता है।

96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली 'कवच' प्रणाली के अंतर्गत 17 स्टेशनों को कवर किया गया है, 23 टावर स्थापित किये गए है और 192 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गयी है। NMS डिवीजन ऑफिस, प्रतापनगर और अहमदाबाद में इंस्टॉल किया गया है। इस सेक्शन में इस प्रणाली के कमीशन होने से संरक्षा में वृद्धि के साथ साथ उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित होगा।